भीतर यह एहसास तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है कि सरकार की विकास योजनाओं के प्रति समाज के बड़े हिस्से की गहरी उदासीनता का ही लाभ तब तक बिचौलियों व भ्रष्ट तंत्र ने उठाया है। लिहाजा, अपने अधिकार व विकास के लिए जनसमुदाय की सक्रियता की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक शनिवार गांव की चौपाल पर समूह के सदस्यों की बैठक होती है। जिसमें गांव की महिलाओं की समस्याओं सहित गांव के विकास को लेकर चर्चा की जाती है। सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ गांव के जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचे इस पर भी रणनीति तैयार होती है। बैठक में प्रत्येक सप्ताह समूह के लेन–देन का हिसाब–किताब भी किया जाता है। गांव के किसान अपना अनाज बाजार मूल्य पर समूह को बेच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसी मूल्य पर खरीद भी सकते हैं। साथ ही समूह की महिलाओं द्वारा गरीब, बेसहारों को लखी अनाज भंडारन समूह के तहत भोजन भी मूहैया कराया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि समूह की महिलाओं द्वारा अत्यंत निर्धन लोगों को लाल कार्ड, मुहैया कराये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे कार्डधारियों को समूह द्वारा लाल कार्ड की दर पर दस किलों अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। संताल, पहाड़िया व कमार जाति वाले इस गांव की महिलाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा में भूख से होने वाली मौतों को रोकने के लिए दिये गये निर्देशों को न तो पढ़ा है और न ही सुना है बावजूद इसके वे इसे रोकने में पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखती हैं।

हस्तक्षेप

संवाद मंथन
रांची, झारखंड

सखी शक्ति नामक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर गांव की ये महिलाएं स्वरोजगार की दिशा में दिन–ब–दिन आगे बढ़ रही हैं। समूह के माध्यम से गांव की महिलाएं ऋण लेकर छोटे–छोटे रोजगार मसलन मूढ़ी उत्पादन, बकरी, मुर्गी, सूअर पालन कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। लक्ष्मी सखी षक्ति की सचिव एवं गांव की सर्वाधिक षिक्षित महिला ममता पुजहारिन बताती हैं कि यह गांव मूढ़ी उत्पादन में पूरे जिले में अव्वल है। एक सौ रूपये मूल्य के धान की मूढ़ी बेचकर स्वयं ममता पुजहारिन प्रत्येक दिन 60 से 70 रूपये कमा लेती है तो दूसरी ओर गांव की अन्य महिलाएं बकरी व मुर्गी पालन कर अपनी आय के ग्राफ को ऊंचा करने मे ंलगी हुई है। इन महिलाओं में आयी इस जागृति को देखकर पुरूष भी इन्हें हरसंभव सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है।

इस तरह जो महिलाएं पहले घर से बाहर कदम तक नहीं रखती थीं, वे आज परिवार और समाज के महत्वपूर्ण फैसलों में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। मानवी के कार्यकर्त्ताओं की अनवरत मेहनत का परिणाम है यह सफलता। संस्था ने पैक्स क तहत चलने वाले रोजगारपरक कार्यक्रम के तहत इन महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। दृढ़ इच्छाशक्ति व लगन की धनी गांव की इन महिलाओं को संस्था ने स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए अभिप्रेरित किया और उन्हें समूह बनाने में मदद की। महिलाओं को उनकी इच्छानुसार रोजगार का प्रशिक्षण दिया गया। समूह के माध्यम से महिलाओं को बचत करने व ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तदुपरांत तीनों समूहों के सदस्यों द्वारा प्रत्येक महीने 20 रुपये जमा किये जाने लगा। तीनों समूहों के पास वर्तमान में कुल दस हजार रूपये हैं। जरूरत पड़ने पर इसके सदस्य दो प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर ऋण लेते हैं। इस प्रकार महिलाओं को अब सूदखोरों के चंगुल से छुटकारा मिल गया है। सूदखोर पूर्व में इन्हें 8 से 10 प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर ऋण देते थे। सबसे खास बात यह है कि समूह की सदस्य रात के 12 बजे भी ऋण ले सकती हैं।

आर्थिक गतिविधियों के साथ ही इन महिला समूहों ने विभिन्न सामाजिक–राजनीतिक मसलों पर भी जागरूकता लाने तथा विकास की प्राथमिकता व दिशा को समझने–समझाने का अभियान शुरू किया है। उनके

हस्तक्षेप

संपादक मंडल
सुधीर पाल
डा. मिथिलेश
विष्णु राजगढ़िया
डा. नीरू जौहरी

संस्करण : अगस्त, 2005

मूल्य : 50 रुपये

प्रकाशक
संवाद मंथन (मंथन युवा संस्थान)
हिन्दपीढ़ी थर्ड स्ट्रीट, रांची-834001
दूरभाष : 0651-2202202
ई-मेल : manthan_ranchi@hotmail.com

टाईपसेटिंग : अभिषेक

आवरण फोटो : तीर्थराज बुढ़िडली
(बिरसा एमएमसी)
रूपांकण : अश्विनी कुमार पंकज

HASTKSHEP

Supported by
PricewaterhouseCoopers(P) Ltd.
Management Consultants

Development Alternatives
111/9, Z Kishnagarh, Basant Kunj,
New Delhi 110070
Tel. : 011-26134103, 26890380
Email : pacsindia@devalt.org

दुमका जिले का गायबथान गांव

परिवार की आर्थिक धुरी बनती महिलाएं

■ दुष्यंत कुमार

सदियों से इन महिलाओं को महज चौके–बरतन और बच्चों संबंधी कार्यों के योग्य समझा जाता था। घर की आर्थिक गतिविधियों में इनकी कोई हैसियत नहीं थी और न ही उनसे कोई राय ही ली जाती थी। लेकिन आज इन महिलाओं ने अपनी सक्रियता व जागरूकता के जरिये स्वतंत्र हैसियत बना ली है और वे अपने परिवार की आर्थिक धुरी बनती जा रही हैं।

दुमका जिले के जामा प्रखंड का गायबथान गांव। 'मानवी' नामक स्वयंसेवी संस्था ने जब यहां महिलाओं को संगठित करने की शुरूआत की थी कौन जानता था कि इतने कम समय में इतनी जबरदस्त सफलता मिलेगी। इस सफलता ने सिर्फ जामा प्रखंड के लिए ही नहीं बल्कि उस पूरे संतालपरगना इलाके के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है जो अविभाजित बिहार के समय से ही राज्य के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी संताल परगना की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में कोई परिवर्त्तन नहीं आया है। नाम मात्र की औद्योगिक गतिविधियों वाले संताल परगना इलाके में लोगों के रोजगार व आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही है। लेकिन सिंचाई की समुचित व्यवस्था के अभाव तथा कृशि के आधुनिक तरीकों व साधनों की अनुपलब्धता के कारण यह क्षेत्र कम उत्पादकता वाले कृशि क्षेत्रों में आता है। यही वजह है कि बड़ी आबादी आज भी निर्धनता के कारण बुनियादी जरूरतें भी पूरा नहीं कर पातीं।

इस पृष्ठभूमि में गायबथान गांव की महिलाओं ने संगठित होकर आर्थिक विकास की दिशा में भागीरथी प्रयास शुरू किये हैं। गांव में तीन–तीन स्वयं सहायता समूहों का गठन कर ये महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में कामयाब रही हैं वरन समाज के विकास में भी अहम् योगदान दे रही है। लक्ष्मी सखी शक्ति, दुर्गा सखी शक्ति एवं कृष्णा

प्रस्तावना

पलामू जिला बंधुआ मजदूरी और भूख के लिए जाना जाता है। पिछले साल इसी पलामू जिले का लेस्लीगंज प्रखंड भूख से मौतों के कारण देश भर में चर्चा का विषय बना था। लेकिन इसी लेस्लीगंज में भूख और दरिद्रता की परिस्थितियों को बनाये रखने वाले बिचौलिया तंत्र के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष की भी मिसाल सामने आयी है। महिलाओं के नेतृत्व में इस संघर्ष ने नयी उम्मीद जगायी है।

लेस्लीगंज प्रखंड के गोपालगंज पंचायत का पथरही गांव। यह पलामू जिला मुख्यालय से अठारह किलोमीटर दूर है। प्रखंड मुख्यालय से महज दो किलोमीटर दूर लगभग दस हजार की आबादी है इस गांव की। गांव में भुइयां और पासवान जाति के लोग रहते हैं तो ब्राह्मण भी। इस गांव के भुइंयां टोला में संपूर्ण ग्राम विकास केंद्र नामक स्वयंसेवी संस्था ने फरवरी 2003 में चौदह महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया था। नाम रखा – ''महिला विकास समिति''। बसंती देवी को इसका अध्यक्ष बनाया गया।

महिला विकास समिति ने महिलाओं के स्वरोजगार व आत्मसम्मान के सवालों के साथ ही विकास की राह में बाधा बने बिचौलिया तंत्र के खिलाफ भी पहलकदमी शुरू कर दी। उनके सामने सवाल यह था कि जब सरकार उनके प्रखंड के विकास के लिए तरह–तरह की योजनाओं तथा सूखे से राहत के लिए विशेष सहायता के दावे कर रही है तो इसका कोई लाभ क्यों नहीं दिखता? सूखा राहत कार्यों के तहत सड़क निर्माण और तालाब निर्माण जैसी योजनाएं भी शामिल थीं। संयोगवश, एक तालाब का निर्माण पथरही गांव में करने की

सुधीर पाल

विषयानुक्रम

बिचौलियों पर भारी पड़ती महिलाएं
6 ■ संजय पांडेय
आत्मनिर्भर हुईं, सूदखोरों से मुक्ति मिली
8 ■ ज्ञान ज्योति
महिलाओं ने बनायी ग्राम सभा, बिचौलियों की नींद हराम
11 ■ हेमंत कुमार
गांव की तस्वीर बदल दी
14 ■ दुष्यंत कुमार
तीस गांवों में जारी है जागृति का नया अभियान
17 ■ शैलेन्द्र सिन्हा
पेड़ से जुड़ी जिंदगी या जंगल बचाने की जिद
20 ■ दिनेश राजगढ़िया/दीपक प्रसाद
राह दिखाने वाले की कमी खल रही है महिलाओं को
23 ■ ज्ञान ज्योति
दलित महिलाओं ने खोला विकास के द्वार
26 ■ सुरेश कुमार निराला
विकास संचार के अनूठे प्रयोग का लाभ ले रहे हैं ग्रामीण
29 ■ ज्ञान ज्योति
मुंदरिया की महिलाएं जगा रही हैं उम्मीद
31 ■ संजय पांडेय
परिवार की आर्थिक धुरी बनती महिलाएं
34 ■ दुष्यंत कुमार

आज उक्त घटना में शामिल लोग जेल में बंद है। पार्वती देवी बताती हैं कि पूरे प्रखंड भर की महिला समितियों को मिलाकर एक संघ का गठन किया गया है जिसमें 40 सदस्य हैं।

जो महिलाएं अब तक हर छोटे–छोटे मामलों के लिए भी पुरुषों पर निर्भर थीं तथा जिनके लिए घर–आंगन की चौखट ही सबसे बड़ी सीमा थी, उनकी निरंतर बढ़ती पहलकदमी ने झारखंड के सर्वाधिक प्रखंड के लिए नयी उम्मीदें जगायी हैं।

■

की आबादी 8645 है। यहां खनिज संपदा भी प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन उस पर आधारित उद्योग व रोजगार के अभाव ने क्षेत्र को बदहाल बना रखा है। इस क्षेत्र के विकास के नाम पर सरकार की ओर से बड़ी विकास राशि खर्च की जा रही है तथा अनगिनत योजनाएं हैं। लेकिन उनका धरातल पर खास असर अब तक नहीं आया है। ऐसे में स्वयंसेवी संस्थाओं के जागरूक कार्यकर्त्ताओं की मदद से बड़ी संख्या में महिलाओं की गोलबंदी ने नयी उम्मीदें जगायी हैं।

इसकी मिसाल पूर्णडीहा पंचायत के मुंदरिया गांव में देखी जा सकती है। इस गांव की आबादी लगभग 800 है। अनुसूचित जनजाति की संख्या लगभग 400 है। इस गांव में एक मध्य विद्यालय व एक उपस्वास्थ्य केंद्र है। यहां लगभग 30 प्रतिशत भूमिहीन है। इस गांव में खेती योग्य भूमि तो है, लेकिन सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्षा के पानी पर ही यहां की खेती पूरी तरह से निर्भर है।

गांव के अधिसंख्य लोग बीमारी व कुपोषण की गिरफ्त में थे। आर्थिक स्थिति अत्यंत ही जर्जर होने के कारण सही समय पर इलाज नहीं करा पाते थे यहां के ग्रामीण। पैक्स कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण ग्राम विकास केंद्र ने इस गांव की कुछ जागरूक महिलाओं को एकत्र कर 'सरस्वती महिला विकास समिति' बनाया। इस समिति का एक ही मुख्य संकल्प है कि बीमारी से अब किसी को मरने नहीं दिया जायेगा। यदि किसी की तबीयत काफी खराब हो जाती है, तो समूह के लोग अपने खर्च पर उसका इलाज कराते हैं। गांव की पन्ना देवी की पुत्री की शादी इसलिए नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दहेज में देने के लिए 3000 रूपये कम थे। जब यह मामला उक्त समिति में आया, तो सभी सदस्यों ने राशि की व्यवस्था कर उसका विवाह कराया।

इस तरह, जागरूक महिलाओं का यह समूह न सिर्फ स्वास्थ्य व स्वरोजगार के लिए प्रयासरत है बल्कि महिलाओं के सम्मान तथा सामाजिक समस्याओं के मामलों में भी कारगर हस्तक्षेप कर रहा है। यहां तक कि महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न तथा अपराधों के मामलों में भी पहलकदमी की जा रही है। समिति की पार्वती देवी बताती हैं कि एक विवाहिता युवती की दहेज लोभियों ने हत्या कर दी थी। थाना में मामला दर्ज नहीं हो रहा था, तब समिति में शामिल महिलाओं ने थाना में दवाब बना कर मामला दर्ज करवाया।

लेस्लीगंज का पथरही गांव

बिचौलियों पर भारी पड़ती महिलाएं

■ संजय पांडेय

पलामू जिला बंधुआ मजदूरी और भूख के लिए जाना जाता है। पिछले साल इसी पलामू जिले का लेस्लीगंज प्रखंड भूख से मौतों के कारण देश भर में चर्चा का विषय बना था। लेकिन इसी लेस्लीगंज में भूख और दरिद्रता की परिस्थितियों को बनाये रखने वाले बिचौलिया तंत्र के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष की भी मिसाल सामने आयी है। महिलाओं के नेतृत्व में इस संघर्ष ने नयी उम्मीद जगायी है।

लेस्लीगंज प्रखंड के गोपालगंज पंचायत का पथरही गांव। यह पलामू जिला मुख्यालय से अठारह किलोमीटर दूर है। प्रखंड मुख्यालय से महज दो किलोमीटर दूर लगभग दस हजार की आबादी है इस गांव की। गांव में भुइयां और पासवान जाति के लोग रहते हैं तो ब्राह्मण भी। इस गांव के भुइंयां टोला में संपूर्ण ग्राम विकास केंद्र नामक स्वयंसेवी संस्था ने फरवरी 2003 में चौदह महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया था। नाम रखा – ''महिला विकास समिति''। बसंती देवी को इसका अध्यक्ष बनाया गया।

महिला विकास समिति ने महिलाओं के स्वरोजगार व आत्मसम्मान के सवालों के साथ ही विकास की राह में बाधा बने बिचौलिया तंत्र के खिलाफ भी पहलकदमी शुरू कर दी। वर्ष 2004 में जब लेस्लीगंज में सूखे का भयंकर प्रकोप हुआ और भूख से मौत की हृदयविदारक खबरें मीडिया की सुर्खियां बनने लगीं, तो इस समूह की महिलाओं ने विकास के बाधक तत्वों को समझने की कोशिश की। उनके सामने सवाल यह था कि जब सरकार उनके प्रखंड के विकास के लिए तरह–तरह की योजनाओं तथा सूखे से राहत के लिए विशेष सहायता के दावे कर रही है तो इसका कोई लाभ क्यों नहीं दिखता? सूखा राहत कार्यों के तहत सड़क निर्माण और तालाब निर्माण जैसी योजनाएं भी शामिल थीं। संयोगवश, एक तालाब का निर्माण पथरही गांव में करने की

पलामू का लेस्लीगंज प्रखंड

मुंदरिया की महिलाएं जगा रही हैं उम्मीद

■ संजय पांडेय

कुछ जागरूक कार्यकर्त्ताओं की पहल तथा कुछ उत्साही महिलाओं की सक्रियता ने पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड में नयी उम्मीदें जगा दी हैं। यह प्रखंड झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए वर्ष 2004 में गंभीर चिंता का विषय बना था, जब भयंकर सूखे व अकाल की वजह से भूखे से मौत की खबरें लगातार आ रही थीं। इस प्रखंड को झारखंड और देश के निर्धनतम क्षेत्रों में गिना जाता है। कृषि ही यहां रोजगार व आय का प्रमुख साधन है जबकि सिंचाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कृषि की उत्पादकता भी काफी निम्न है। गत वर्ष मानसून देर से आने के कारण क्षेत्र की लगभग नब्बे प्रतिशत कृषि योग्य भूमि परती रह गयी थी। इस प्रखंड में बड़ी आबादी भूमिहीन दलितों की है जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं। कृषि कार्यों में मजदूरी ही उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। रोजगार के अभाव में उन्हें भयावह गरीबी की अवस्था से गुजरना पड़ता है तथा कंद–मूल खाकर, शहरों में पलायन करके, रिक्शा चलाने जैसे कार्यों के जरिये न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने हेतु विवश होना पड़ता है।

इस प्रखंड में महिलाओं की सक्रियता व जागरूकता ने नया रंग दिखाया है। दिलचस्प तथ्य यह है कि इस प्रखंड में महिलाओं की तादाद पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। जबकि पूरे राज्य के आँकड़े देखें तो 1000 पुरुषों के अनुपात में 941 महिलाएं हैं। लेस्लीगंज प्रखंड की कुल आबादी 79345 है। इनमें महिलाओं की संख्या 38975 तथा पुरुषों की संख्या 40370 है। लिहाजा, आबादी का बड़ा हिस्सा होने के बतौर महिलाओं ने क्षेत्र के विकास का कारवां एक बार शुरू कर दिया तो इसकी रफ्तार कम न होगी।

लेस्लीगंज प्रखंड में 16 पंचायत व 143 गांव है। अनुसूचित जनजाति

पिछले दो साल से संचालित इन सूचना केंद्रों से ग्रामीणों को क्या लाभ हुआ है? यह जानने की कोशिश की गयी, तो धनयडीह के लीलो राणा ने बताया कि पहले ग्रामीणों को गांव के विकास के लिये सरकार द्वारा संचालित विकास के लिए आने वाली विकास योजनाओं में ग्रामीणों की भागीदारी नहीं हो पाती थी। प्रायः सभी योजनाओं में बिचौलिये हावी रहते थे और जैसे–तैसे कार्य कराकर प्राक्कलन की अधिकांश राशि डकार जाते थे। पर ग्रामीण अब योजना संबंधी हर बात की जानकारी रखते हैं और प्राक्कलन के अनुरूप कार्य करवाते हैं। ग्रामीण महिला मोहिनी देवी बताती हैं कि गांव की महिलाएं भी सूचना केंद्र पहुंच अपने संबंधी जानकारियां प्राप्त करती हैं। वहां न केवल सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, बल्कि गांव, समाज और परिवार के विकास पर भी चर्चा होती है।

वे बताती हैं कि गांव की अनपढ़ महिलाओं को यह भी पता नहीं था कि सरकार ने महिलाओं के उत्थान और विकास के लिये क्या योजना चला रखी है। महिलायें चूल्हा–चौकों तक सीमित रहकर पुरूषों की गुलामी करना ही अपनी नियति मानती थीं। पर सूचना केंद्र से उन्हें मालूम हुआ कि महिलायें केवल घर तक ही सीमित रहने के लिए नहीं हैं, बल्कि बाहर भी उन्हें कई तरह के अधिकार प्राप्त हैं।

एक ऐसे समय में, जबकि देश एवं राज्य में सूचना के अधिकार को लेकर व्यापक जागरूकता आ चुकी हो तथा इसके लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान किये जा रहे हों, गिरिडीह जिले के इन सूचना केंद्रों की उपयोगिता काफी स्पष्ट रूप में नजर आती है। वास्तव में अगर सूचना के अधिकार को अमली जामा पहनाना हो, तो ऐसे सूचना केंद्रों की इसमें अहम् भूमिका होगी।

■

योजना स्वीकृत हुई। इस काम के अभिकर्त्ता का चयन आमसभा के माध्यम से किया जाना था। इसके लिए पथरही गांव में आमसभा हुई। लेकिन बिचौलियों को लाभ दिलाने की नीयत से आम सभा में काफी अनियमितता हुई। हर आमसभा की अमूमन यही कहानी है। लेकिन पथरही की बात अब कुछ और थी। वहां महिला विकास समिति थी और उसके भीतर यह जबरदस्त चेतना आ चुकी थी कि उनके हक से कोई खिलवाड़ न करे। लिहाजा, अध्यक्ष बसंती देवी के नेतृत्व में महिला विकास समिति ने आमसभा में धांधली का जमकर विरोध किया। यहां तक कि प्रशासन को बाध्य होकर नये सिरे से आमसभा का आयोजन करना पड़ा। इसमें फिर कोई अनियमितता न हो, इसके लिए बीडीओ, सीओ और डीडीसी तक को भारी पुलिसबल के साथ मौजूद होना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि आमसभा ने महिला विकास समिति को ही एक लाख बहत्तर हजार रूपयों में उस तालाब के निर्माण का जिम्मा सौंप दिया। इस तरह बिचौलियों को बुरी तरह मात खानी पड़ी।

महिला विकास समिति की इस सफलता ने आसपास के इलाकों की महिलाओं में काफी चेतना पैदा की है। अब वे आमसभा में पूरी बुलंदी के साथ अपनी बात कह रही हैं। वे समझ चुकी हैं कि एकता में काफी बल है। पथरही गांव के लोगों का मुख्य पेशा खेती, मजदूरी व व्यवसाय है। इस गांव में दो टोले हैं। एक है भुइयां टोला दूसरा है ब्राह्मण टोला। पथरही के अधिकांश भुइयां व हरिजन भूमिहीन है। लिहाजा उन्हें मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। काम नहीं मिलने पर अन्यत्र पलायन भी करना पड़ता है। पंजाब, उत्तरप्रदेश, हरियाणा इत्यादि राज्यों में पलायन करना काफी तकलीफदेह अनुभव है। अब कोई ग्रामीण नहीं चाहता कि पलायन की नौबत आये। वे अपने गांव में ही मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं। महिला विकास समिति की गतिविधियों ने ग्रामीणों में भी एक नयी हलचल पैदा की है। उन्हें लगता है कि जब महिलाएं एकजुट होकर इतना कुछ कर रही हैं, तो वे भी कुछ कर सकते हैं।

इस तरह पथरही गांव की महिलाओं की एकता व चेतना ने पूरे इलाके में बदलाव की नयी उम्मीद पैदा की है। जबकि भ्रष्ट अधिकारियों व बिचौलिया तंत्र को अपनी मनमानी पर अंकुश लगने की चिंता सता रही है।

■

शीतलपुर की दलित महिलाएं

आत्मनिर्भर हुईं, सूदखोरों से मुक्ति मिली

■ ज्ञान ज्योति

महज तीन बरसों में मानो दुनिया ही बदल गयी है इनकी। अब तो देगनी देवी के चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास नजर आता है कि जैसे हर बाधा को दूर कर मंजिल तक पहुंच जायेंगी। देगनी देवी बताती हैं कि किस तरह पहले उनके इलाके की महिलाओं को सूदखोरों के शोषण और जुल्म का शिकार होना पड़ता था। प्रेमचंद की कहानियों में भारतीय किसानो के कर्ज फांस में डूबे होने की जिन भयावह स्थितियों का चित्रण मिलता है, उसका जीवंत उदाहरण देखा जा सकता है देगनी देवी जैसी महिलाओं की जिंदगी में। कलावती देवी, तारा देवी, दुर्गा देवी, मो0 कमला, बसंती देवी, रेखा देवी भी बताती हैं कि अब सूदखोरों से मुक्ति ने कितनी बड़ी राहत दिलायी है। पहले किसी भी आर्थिक संकट या आफत–विपत के मौके पर महाजनों और सूदखोरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। भारी ब्याज पर ली गयी रकम के कारण अधिकांश परिवारों को भयंकर कर्ज में उलझ जाना पड़ता था। महाजनों को समय पर पैसा नहीं देने से वे मारपीट व अपमानित करने पर उतारू हो जाते। लोगों की अधिकांश कमाई ब्याज चुकाने में ही नष्ट हो जाती, मूल कर्ज बरकरार रहता। लेकिन अब पैक्स कार्यक्रम के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने इतनी आत्मनिर्भरता ला दी है कि किसी भी जरूरत के मौके पर अपनी संचित राशि का ही तत्काल एवं सम्मानपूर्वक उपयोग कर लें। बाद में न्यूनतम ब्याज सहित लौटा दें।

झारखंड के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत शीतलपुर गांव के दलित टोले की महिलाओं ने इस आत्मनिर्भरता के जरिये जबर्दस्त आत्मविश्वास और आत्म–सम्मान हासिल किया है। इन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि महिलाएं जितनी कुशलता से घर के कामों को संभालती हैं, अगर मौका मिले तो वे पुरूषों के वर्चस्व वाले अन्य काम भी कर सकती हैं। प्रगतिशील युवा केंद्र

गिरिडीह में सूचना केन्द्र

विकास संचार के अनूठे प्रयोग का लाभ ले रहे हैं ग्रामीण

■ ज्ञान ज्योति

सामाजिक विकास में संचार के महत्व को पूरी दुनिया में समझा व परखा चुका है। इसके बावजूद अब तक झारखंड के बड़े हिस्से में अशिक्षा, संचार के साधनों की अनुपलब्धता तथा जागरूकता के अभाव के कारण विकास की राह में बाधाएं कायम है। ऐसे में, झारखंड के गिरिडीह जिले में ग्रामीणों को महत्वपूर्ण सूचनाओं से लैस करने के लिए पिछले दो साल से चल रहे प्रयासों को एक मिसाल के बतौर देखा जा सकता है। स्वयंसेवी संस्था 'जागो फाउंडेशन' का यह प्रयास 'विकास संचार' का एक अनूठा प्रयोग है। संस्था ने पैक्स कार्यक्रम के तहत गिरिडीह सदर प्रखंड की तीन पंचायतों वनयडीह, मदनपुर तथा जीतपुर में एक–एक सूचना केंद्र खोले हैं। दो वर्षों से इन सूचना केंद्रों में ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करायी जा रही हैं। इन सूचना केंद्रों में प्रतिदिन अखबार तथा पत्रिकाएं आने के कारण इनका आकर्षण काफी बढ़ गया है। क्योंकि क्षेत्र के लोगों की आर्थिक हैसियत तथा जागरूकता का स्तर ऐसा है कि नियमित रूप से अखबार मंगाने व पढ़ने वालों की संख्या नगण्य है। लेकिन इन सूचना केंद्रों में नियमित रूप से अखबार एवं पत्रिकाएं आने का नतीजा यह हुआ है कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों में अखबार पढ़ने की रूचि जागृत हुई है।

इन सूचना केंद्रों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक विषयों की पुस्तकें भी उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी देने वाली पुस्तकें भी इन सूचना केंद्रों में देखी जा सकती है। खासतौर पर गिरिडीह जिले की सरकारी योजनाओं तथा झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों को भी इन केंद्रों में उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है।

पर विवाद शुरू हुआ। पहले मंदिर से जुड़े एक समुदाय विशेष के लोग जुटे और दलित विरोधी परंपरा के समर्थन में अपना स्वर मुखर कियपा। इस पर दिलत महिलाएं उग्र हो गयी। इन महिलाओं का साहस देखकर दलित समुदाय की अन्य महिलाएं एवं पुरुष भी एकत्रित हो गये। विवाद बढ़ गया और बात थाना तक पहुंच गयी।

दलित महिलाअें ने थाना में मंदिर की पुजारिन एवं मंदिर से जुड़े प्रमुख लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी। इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब महिलाओं ने स्थानीय थाना व प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए इस मामले को लेकर सड़क पर उतरने का मन बनाया। उन्होंने पंचायत मुख्यालय पर धरना दिया और फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी।

अब यह महज एक गांव का मामला नहीं रह गया बल्कि इसकी अनुगूंज पूरे प्रखंड स्तर पर सुनायी पड़ने लगी। यहां तक कि जिला मुख्यालय के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। पूरे इलाके के न्याय पसंद लोगों की सहानुभूति इस आंदोलन के साथ थी।

एक माह तक लगातार आंदोलन के बाद अंततः स्थानीय प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और मंदिर से जुड़े प्रमुख लोगों एवं दलित समुदाय के बीच पंचायत बुलायी। काफी हो—हंगामा के बाद मंदिर में दलितों के प्रवेश से पाबंदी हटी। इस तरह वर्ष 1999 से इस मंदिर में दलितों को अपने प्रवेश का अधिकार मिला। इस आंदोलन में प्रयास संस्था के महेंद्र रविदास, राजकुमार रविदास, अजय रविदास, भीम रविदास, रामेश्वर रविदास, स्व0 योगेश रविदास आदि ने भरपूर सहयोग किया।

इस सफलता ने करियातपुर के दलितों के भीतर आत्मसम्मान तथा बराबरी का जोश दुगुना कर दिया। उनके भीतर यह एहसास कायम हुआ कि एकजुट होकर पहलकदमी लेने से आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है। इसी एहसास का परिणाम है कि 'प्रयास' के कार्यकर्त्ताओं को पैक्स कार्यक्रम के तहत इस गांव के दलित समुदाय के विकास के लिए अनगिनत कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करने में सफलता मिली है। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वावलंबन की दिशा में प्रयास तेज कर दिये हैं।

■

नामक स्वयंसेवी संस्था ने लगभग तीन साल पहले जब इस इलाके की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के बतौर इकट्ठा करना शुरू किया था तो किसी को एहसास तक नहीं था कि इतने कम समय में इतनी सफलता हाथ लग जायेगी। शुरूआत में तो महिलाओं में तरह—तरह के सवाल थे, संदेह था, शंकाएं थीं, ठगे जाने का भय था, हिचक थी। लेकिन प्रगतिशील युवा केंद्र के कार्यकर्त्ताओं ने निरंतर व जीवंत संपर्क के जरिये जल्द ही महिलाओं का यह भरोसा जीत लिया कि उनका उद्देश्य समाज को विकास की एक नयी दिशा प्रदान करना है। फिर तो देखते—ही—देखते महिलाओं की गोलबंदी तेजी होती गयी और दस महिला समूहों का गठन हो गया। हरेक समूह में दस—बारह महिलाएं। हर समूह की महिलाओं ने अपनी दस—पांच रुपयों की छोटी—छोटी बचत के जरिये अच्छी—खासी राशि जमा कर ली। यहां तक की कुछ समूहों के पास यह राशि बारह हजार रुपयों तक हो चुकी है। इस राशि का उपयोग किसी भी महिला को किसी भी जरूरत के मौके पर बतौर न्यूनतम ब्याज तथा महिलाओं को स्वरोजगार के जरिये अपने पैरों पर खड़ा करने के कार्य में किया जा रहा है। अब तक इन समूहों की बाइस महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। इनमें से नौ महिलाएं बकरी पालन, पांच महिलाएं सूअर पालन, दो महिलाएं ईंट निर्माण तथा एक महिला सब्जी व्यवसाय से जुड़ी हैं जबकि तीन महिलाएं विभिन्न प्रकार की दुकानें चला रहीं हैं। स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं ने अपने परिवारों की आर्थिक हालत में सुधार लाकर जहां प्रगति की एक नयी उम्मीद जगायी है, वहां सूदखोरों के चंगुल से निकलने में भी मदद की है। पहले ये महिलाएं अपनी छोटी—छोटी जरूरतों के लिए भी घर के पुरुषों पर निर्भर थीं। लेकिन अब अपनी कमाई होने के कारण यह निर्भरता कम होती जा रही है।

पैक्स कार्यक्रम के तहत दलित महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाये जाने से महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ ही सामाजिक —राजनीतिक स्तर पर जागरूक होने का भी अवसर मिलता है। गत लोकसभा व विधानसभा चुनावों में यहां की महिलाओं ने पहली बार अपनी मर्जी से अपने पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला था। इसके पूर्व महिलाएं कुछ राजनैतिक पार्टियों के दलालों के दबाव में आकर उनके कहे अनुसार वोट देती थी। पहले महिलाओं को अपने वोट की कीमत मालूम नहीं थी। उनका कहना था कि मेरे

एक वोट देने से क्या होनेवाला है ? चाहे जिसको दें। चुनाव में वोट की ठेकेदारी करनेवाले दलाल और बिचौलिये किस्म के लोग महिलाओं की इसी सोच का नाजायज फायदा उठाते हुए उन्हें बहला–फुसलाकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डलवाते थे, पर इन चुनावों में दलालों की एक न चली, महिलाओं ने अपनी इच्छानुसार मतदान किया।

राजनीतिक जागरूकता का आलम ये है कि महिलाएं अब पंचायत चुनाव को लेकर भी काफी सक्रिय हो गयी हैं। हाल ही में शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर समूह की महिलाओं ने बीते वर्ष जिला और प्रखंड मुख्यालय में जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं अपने अधिकारों और गांव–मुहल्ले के विकास को लेकर भी महिलाएं काफी सजग हुई हैं। महिलाओं ने बीते वर्ष लगातार कई दिनों तक प्रखंड और जिला स्तर पर आंदोलन चलाया था और अधिकारियों से अपने गांव व मुहल्ले का विकास और बुनियादी सुविधाएं बहाल करने की मांग रखी थी। महिलाओं को अधिकारियों ने उनकी मांगों को यथासंभव पूरा करने का आश्वासन दिया। तब जाकर महिलाओं ने आंदोलन बंद किया। बहरहाल, सदियों से महिलाओं को अबला समझे जाने के मिथक को यहां की महिलाओं ने तोड़ा है। इन्होंने साबित कर दिया है कि महिलाएं केवल घर परिवार तक ही सीमित न रहकर बाहर के कामों को भी बखूबी अंजाम दे सकती हैं।

■

पर पाबंदी थी। इस गांव की कुल आबादी लगभग 2500 है। इस आबादी में पचास फीसदी दलित हैं। शेष आबादी में उच्च जाति के लोग वैश्य, प्रजापति, कुम्हार आदि हैं। गांव में लगभग 1300 हरिजन हैं। इनमें ज्यादातर रविदास जाति के हैं। मुख्य रूप से ये मजदूरी करते है। गांव में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के कारण दलित मंदिर में अपने प्रवेश के अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा पाते थे। यही नहीं, इस गांव के संपन्न व उच्च जाति के लोग इन दलितों पर मजदूरी आदि के मामले को लेकर आये दिन अत्याचार भी करते थे। यह सिलसिला वर्ष 1998 तक चलता रहा।

इस बीच 'प्रयास' से जुड़े कार्यकर्त्ताओं ने इस क्षेत्र में सामाजिक चेतना लाने तथा गैर बराबरी की सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने एवं जनसमुदाय को गोलबंद करने का अभियान प्रारंभ कर दिया था। दूसरी ओर, खुद समाज के इन वंचित तबकों के भीतर बदलाव आ रहा था।

नब्बे के दशक में जब शिक्षा का प्रसार बढ़ा और दलित समुदाय में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी तब धीरे–धीरे ये लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने लगे। इस गांव में नब्बे के दशक तक दलितों में शिक्षा का स्तर बेहद निम्न था। मात्र 10 प्रतिशत लोग साक्षर थे। नब्बे के बाद इनकी साक्षरता दर में तेजी से सुधार हुआ। आज लगभग 50 प्रतिशत दलित साक्षर हैं। इनमें महिलाओं का भी प्रतिशत बराबर है। गांव के मंदिर में अपने प्रवेश के अधिकार और अपने मान–सम्मान की रक्षा के लिए जब यहां के दलित समाज में जागरूकता आयी तो कुछ लोग आगे आये, पर छिटपुट विरोध से कोई परिणाम सामने नहीं आया। कुछ जागरूक दलित महिलाओं ने अपना प्रयास जारी रखा।

वर्ष 1999 में गांव के दलित समुदाय की रेशमी देवी, भतनी देवी, सीता देवी, दुलारी देवी आदि महिलाओं ने आपस में एकजुट होकर मंदिर में प्रवेश करने का फैसला किया। वे समय निर्धारित कर एक धार्मिक अनुष्ठान के क्रम में नये वस्त्र आदि लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर की पुजारिन जो स्वयं एक महिला हैं, ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। महिलाओं ने पहले तो पुजारिन को नम्रता से समझाया कि एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंदिर में नये वस्त्र चढ़ाना आवश्यक है। अतः उन्हें नहीं रोके। इतना होने पर पुजारिन नहीं मानी। इस

हजारीबाग का करियातपुर गांव

दलित महिलाओं ने खोला विकास के द्वार

सुरेश कुमार निराला

हमारे देश में सदियों से चली आ रही वर्ण–व्यवस्था के तहत छूआछूत की भावना ने आबादी के बड़े हिस्से को हर मामले में वंचित एवं अविकसित रखा है। लेकिन जहां पर वंचित लोगों ने साहस करके पहलकदमी ली, वहां विकास की नयी संभावनाओं के रास्ते खुल गये हैं। एक ऐसा ही गांव है करियातपुर।

झारखंड राज्य के हजारीबाग जिलांतर्गत बरही प्रखंड के इस छोटे से गांव के दलित वर्षों से पूरे गांव की उपेक्षा और प्रताड़ना के शिकार थे। गांव के एक सार्वजनिक मंदिर (देवस्थान) में दलितों के प्रवेश तक पर रोक थी। यह स्थिति यहां वर्ष 1998 तक कायम थी। परंतु वर्ष 1999 में यहां की कुछ दलित महिलाओं ने इस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और मंदिर में अपने प्रवेश का अधिकार हासिल किया। यही नहीं उन्होंने गांव में अपने विकास के नये मार्ग भी बनाये।

एक बार जब दलित महिलाओं ने एकजुट होकर अपने सम्मान और बराबरी के हक की रक्षा कर ली, तो अब विकास की दिशा में उनके कदम तेजी के साथ बढ़ चले हैं। आज इस गांव की महिलाएं पैक्स कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह के बतौर संगठित होकर अपनी आत्मनिर्भरता, शिक्षा, सम्मान और स्वरोजगार की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। यह सारा कुछ संभव हो पाया है 'प्रयास' नामक स्वयंसेवी संस्था के कर्मठ कार्यकर्त्ताओं के अथक प्रयासों से।

बरही प्रखंड मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर करियातपुर गांव में एक सार्वजनिक मंदिर (देवस्थान) है। इसका निर्माण साठ के दशक में यहां के व्यवसायी वर्ग के कुछ समाज सेवियों ने किया था। तब से इस मंदिर में सिर्फ उच्च जाति के लोग ही पूजा–पाठ करने जाते थे। इसमें दलितों के प्रवेश

गुमला जिले का कुलमुंडा गांव

महिलाओं ने बनायी ग्राम सभा, बिचौलियों की नींद हराम

हेमंत कुमार

यहां तक आते–आते सूख जाती हैं नदियां
हमें मालूम है पानी कहां ठहरा होगा?

इन पंक्तियों का मर्म जानना हो तो झारखंड के गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के गांवों में चल रही सरकारी योजनाओं को देखा जा सकता है। इस जिले में जनजातीय आबादी की बहुलता के कारण विशेष विकास योजनाओं के प्रावधान के बावजूद दिल्ली और रांची से चलनेवाली नदियों का पानी रास्ते में ही सूख जाया करता है। हालांकि अब एक बड़ा फर्क यह आया है कि कुलमुंडा गांव की महिलाओं ने इसे बखूबी समझ लिया है कि उनके हिस्से का पानी कहां ठहरा रह जाता है। इसी चेतना के कारण कुलमुंडा गांव की महिलाओं ने घरों की चौखटें लांघकर प्रखंड मुख्यालय का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। गांव के आठ टोलों की महिलाओं ने मिलकर ग्रामसभा का गठन किया है। अब तक जिन विकास योजनाओं पर बिचौलियों का कब्जा था, उन योजनाओं को ग्राम सभा के माध्यम से कराने की मांग तेज कर दी गयी है। प्रखंड अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि ग्रामीणों के हिस्से की विकास राशि की बंदर बांट नहीं होने दी जायेगी। ग्राम सभा ने यह प्रण कर लिया है कि अब किसी भी काम के मार्फत ही हर काम किया जायेगा। पैक्स कार्यक्रम के तहत 'आइडस' नामक स्वयंसेवी संस्था की पहल का नतीजा है कि आज कुलमुंडा गांव के लोगों ने विकास की दिशा में गंभीर प्रयास करते हुए अपने हक की लड़ाई शुरू की है।

कुलमुंडा मौजा के तहत बेहराटोली, कांसीटोली, बेंगाटोली, वैरीटोली, खूंटीटोली, मरियमपुर, बक्सपुर, ड्रेसिंग कोना, खटखोर, रूकरूम व खास कुलमुंडा आते हैं। ग्राम सभा मे ग्राम विकास समिति, सार्वजनिक संपदा समिति, कृषि समिति, ग्राम रक्षा समिति, आधारभूत संरचना समिति, शिक्षा समिति,

सामाजिक न्याय समिति तथा निगरानी समिति आदि शामिल हैं। ग्राम सभा का अध्यक्ष हरिमोहन बेगा व अशोक लकड़ा, उपाध्यक्ष माधुरी देवी, सचिव बिरसा मिंज, कोषाध्यक्ष विलियम खाखा व विरेंद्र उरांव को बनाया गया है। बीते दिनों कुलमुंडा मौजा के सभी आठ टोलों के ग्रामीणों की सभा में सैकड़ों महिला व पुरूष षामिल हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा के माध्यम से ही फैसले होंगे कि किस प्रकार गांव का सर्वांगीण विकास किया जाये एवं किन–किन विकास योजना को गांव में लागू करने दिया जाये। विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त होने के बाद महिलाओं में तेजी से आ रही जागरूकता का परिणाम है कि अब वे हर योजना की बखूबी समीक्षा कर रही हैं। महिलाओं में इस बात को लेकर काफी रोष है कि आज तक गांव में लोगों को इंदिरा आवास व वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा प्राप्त नहीं है। इन योजनाओं का लाभ वैसे लागों को दिया जा रहा है जिन्हें पूर्व से ये सुविधाएं प्राप्त हैं या बिचौलियों से सांठ–गांठ है। ग्राम सभा की महिला कौशल्या देवी ने बताया कि अब हमलोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। अब हम विकास कार्यों का लाभ बिचौलियों के हाथों में नहीं जाने देंगे।

कौशल्या देवी ने बताया कि ग्रामसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिये बैंक में खाता खोल दिया गया है तथा रजिस्टर एवं खाता पुस्तिका में कार्यवाही दर्ज की जा रही है। हमलोग आठ टोलों में क्रमशः प्रतिमाह एक टोले में बैठक करते हैं तथा उन टोलों को आदर्श ग्राम बनाने पर चर्चा होती है। गांव में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। बिजली, पानी, सड़क की विकट समस्या है जिसके लिये जिला प्रशासन को अवगत कराया जायेगा। जंगल उजड़ रहे हैं। महिलाओं ने अब ठाना है कि गांव की महिलाएं स्वयं जंगल में वृक्षारोपण का कार्य करेंगी जिससे गांव में पेयजल की समस्या न हो, जंगल हरा–भरा रहे, ग्रामीणों को जलावन की लकड़ी सहित अनेक प्रकार के फलों की औषधियां प्राप्त हो सके। ग्राम सभा की महिलाएं विकास कार्यों की जांच कर रही है और उनकी गुणवत्ता पर सवाल भी उठाती है जिसके कारण बिचौलियों व प्रखंड मुख्यालय के पदाधिकारियों की नींद उड़ने लगी है। बिचौलिये संगठित महिला–पुरूषों को तोड़ने में लगे रहते हैं ताकि ग्राम सभा के सदस्य मेल–मिलाप से नहीं रह सकें लेकिन कुलमुंडा मौजा के ग्रामीण आपसी एकता व सौहार्द के साथ कार्य कर रहे हैं। महिलायें जहां गांव के विकास हेतु बढ़

से इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है।

समूहों से जुड़ी महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें पहले की तरह अब भी समुचित मार्गदर्शन मिले ताकि जिस उद्देश्य के तहत वे एकजुट हुईं, उन्हें पूरा किया जा सके। महिलाओं का कहना है कि विकास योजनाओं में बिचौलिये के हावी रहने के कारण गांव का विकास अवरूद्ध है। गांव में आनेवाली योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती और न ही आम सभा में महिलाओं से कोई विचार लिया जाता है। यहां तक कि उन्हें आम सभा में बुलाया भी नहीं जाता है। संस्था के लोग पहले इन सब मुद्दों पर भी महिलाओं को गोलबंद कर आंदोलन छेड़ने की बात कहते थे। पर संस्था वाले अब इन सब बातों पर चर्चा भी नहीं करते। कभी–कभार संस्था के कार्यकर्त्ता गांव आते हैं और रिपोर्ट लेकर चले जाते हैं। बेहतर हो कि एक बार पुनः नये सिरे से इन महिलाओं को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये।

जहमत संस्था की ओर से नहीं उठायी जा रही है। परिणामतः संस्था द्वारा जिस उद्देश्य से महिलाओं को संगठित कर, यहां स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, वह पूरा होगा। इस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है।

प्रारंभ में 'प्रगतिशील युवा केंद्र' के कार्यकर्त्ताओं ने काफी उत्साह एवं कर्मठता का परिचय देते हुए महिलाओं को तेजी से गोलबंद किया। इसी का परिणाम है कि उसे इस गांव में चार समूहों के गठन में सफलता मिली जिनके नाम हैं– ज्ञान ज्योति समूह, लक्खी समूह, विकास समूह और जागृति समूह है। समूह के सदस्यों की संख्या क्रमशः 10, 11, 12 और 12 है। अबतक प्रत्येक समूह में क्रमशः 8000, 2000, 4000 और 3500 रुपये महिलाओं द्वारा बचत किये जा चुके हैं। पैसे की बचत कर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिये कुछ रोजगार करना चाह रही हैं। पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। समूह से जुड़ने और पैसे जमा करने का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। समूह की जो महिलाएं थोड़ी–बहुत पढ़ी–लिखी और तेज–तर्रार हैं, उन्हें तो इसका लाभ कमोबेश मिल रहा है लेकिन अन्य महिलाएं लाभ से वंचित रह रहीं हैं। ज्ञान ज्योति समूह की दो महिलाओं ने बैंक से ऋण लिया है। महिलाओं द्वारा बैंक को इस ऋण की अदायगी नहीं किये जाने से समूह की अन्य महिलाओं को ऋण नहीं मिल पा रहा है। जिस कारण शेष महिलाओं में रोष व्याप्त है। इन महिलाओं का कहना है कि समूह में 1–2 महिलाओं का ही वर्चस्व है। ये महिलाएं दूसरी महिलाओं की मदद करने के बजाय वे अपना निजी स्वार्थ पूरा करने में लगी रहती हैं। संस्था वाले भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले संस्था के लोग हर बैठक में भाग लेकर उचित दिशा–निर्देश देने के साथ–साथ महिलाओं की समस्याओं को सुनते और उसके समाधान पर विचार–विमर्श करते पर अब तो संस्था के लोग भी आना छोड़ दिये हैं जिस कारण महिलाएं ठगी सी महसूस करने लगी हैं। ज्ञान ज्योति समूह की पार्वती देवी, लक्खी समूह की लीला देवी, विकास समूह की गीता देवी तथा जागृति देवी की सावित्री देवी, सुनीता देवी, गीता देवी आदि महिलाओं ने बताया कि वे सब संस्था के कार्यकर्त्ताओं की बातों से प्रभावित होकर आत्मनिर्भर बनने के लिये समूह बनायीं। महिलाएं सिलाई, पापड़, अचार, अगरबत्ती, मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण लेकर इसे रोजगार के रूप मे अपनाना चाहती हैं। इन्होंने अपने विचारों से संस्था को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन संस्था की ओर

चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इन्हें देख कर पुरूष भी उनके साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं। ग्राम सभा की महिलाओं का हौसला बढ़ गया है तथा वे एक–दूसरे का सहयोग लेते हुए कार्य कर रही हैं। पैक्स प्रोग्राम के तहत उन महिलाओं को जागरूक करने के लिये समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह पंचायती राज, लिंग संवेदनशीलता आदि चार प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। पहले जो महिलाएं अपने हक व अधिकार जानती नहीं थी। उन्हें संविधान के 73वें संशोधन के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही उन्हें ग्राम सभा के हक व अधिकार के विषय में विस्तृत रूप से बताया गया तब आज ग्राम सभा की महिलाएं संगठित होकर कार्य कर रही हैं। पैक्स के द्वारा ग्राम सभा की साप्ताहिक बैठक करायी जा रही है। गांव में कैसे विकास कार्य करना है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अगर महिला अशिक्षित हो तो उसे जागरूक करने के लिये मनोरंजन खेल एवं नुक्कड़ सभाओं का सहारा लिया गया है और ये महिलाएं भी ग्राम सभा से जुड़ रही हैं। गांव में परंपरागत वैगा पहान को भी ग्राम सभा के विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

महिलाओं की एकजुटता तथा पहलकदमी के कारण बिचौलियों एवं अधिकारी भयभीत हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्राम सभा की ओर से महिलाओं ने जब प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रखंड की विकास योजनाओं की जानकारी मांगी तो उन्होंने सकारात्मक रवैया अपनाने के बदले उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया। दूसरी ओर, बिचौलियों द्वारा ग्रामीणों को बरगलाने तथा ग्राम सभा की बैठकों को असफल करने की कोशिशों के भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन महिलाएं यह जान चुकी हैं कि वे जिस राह पर बढ़ रही हैं, उस राह पर इन बाधाओं से निपटना ही होगा। यही कारण है कि महिलाओं की एकता अब भी कायम है और उतना ही दृढ़ संकल्प भी कि हम हर बाधा को दूर ठेलते हुए आगे बढ़ते जायेंगे।

शांति की पहल ने
गांव की तस्वीर बदल दी

■ दुष्यंत कुमार

झारखंड की उपराजधानी है दुमका। इस जिले के जामा प्रखंड का निश्चितपुर गांव आज विकास की एक नयी राह तलाश रहा है। जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी महज पंद्रह किलोमीटर है। लेकिन निश्चितपुर की शांति मुर्मू को अपने इस गांव से दुमका जिला मुख्यालय तक सफर तय करने में बरसों लग गये। वजह सिर्फ यह है कि कोई यह राह दिखाने वाला नहीं था कि गांव और ग्रामीणों के लिए सरकार ने कौन–सी योजनाएं बना रखी हैं तथा उनका लाभ किस तरह उठाया जा सकता है? पिछले वर्ष जब गांव की महिलाओं ने इसका लाभ उठाना चाहा। आंगनबाड़ी सेविका तथा एएनएम के पास महिलाओं ने खूब गुहार लगायी। कोई नतीजा नहीं निकला। यह देख गांव की जागरूक महिला शांति मुर्मू ने तय कर लिया कि किसी भी तरह इन महिलाओं को जायज हक दिलाया जाये। संयोगवश, उसी दौरान 'मानवी' नाम की स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्त्ताओं से इस संबंध में जरूरी जानकारियां मिल गयी।

बस, फिर क्या था? अपने धुन की पक्की शांति मुर्मू ने पांचों महिलाओं को साथ लेकर सीधे दुमका की रहा पकड़ ली। उपविकास आयुक्त से मिली और सारी शिकायतें दर्ज करा दीं। आंगनबाड़ी सेविका तथा एएनएम के गांव में न पहुंचने की भी शिकायत कर दी गयी। डीडीसी ने महिलाओं की सभी शिकायतों पर कार्रवाई का आदेश दिया तथा मातृत्व लाभ योजना की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दे दी। शहर और सरकारी दफ्तर में पहली बार कदम रखते ही जरूरतमंद महिलाओं को वाजिब हक दिलाने में मिली इस सफलता से शांति मुर्मू का हौसला दोगुना हो गया। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने का काम तेज कर दिया। कुछ ही समय के भीतर जबरदस्त सफलता भी मिली। दरअसल पांच महिलाओं को मातृत्व

गिरिडीह का दिघरिया खुर्द गांव
राह दिखाने वाले की कमी खल रही है महिलाओं को

■ ज्ञान ज्योति

सामाजिक परिवर्तन एक लंबी, जटिल एवं कष्ट साध्य प्रक्रिया है जिसमें अनवरत प्रयास से ही सफलता हासिल की जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन से जुड़े कार्यकर्त्ताओं एवं संस्थाओं की जरा–सी शिथिलता के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसका उदाहरण गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में देखा जा सकता है। दिघरिया खुर्द गांव में बनाये गये महिलाओं के चार स्वयं सहायता समूहों के विकास की गति फिलहाल थम–सी गयी है। जिन महिलाओं ने काफी उत्साह के साथ समूह बनाकर पहलकदमी की थी, वे फिलहाल सही मार्गदर्शन व नेतृत्व के अभाव में कोई ठोस सार्थक कार्य नहीं कर पा रही हैं।

इन चार महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन पैक्स कार्यक्रम के तहत 'प्रगतिशील युवा केंद्र' नामक स्वयंसेवी संस्था द्वारा कराया गया था। महिलाओं ने इस प्रयास का भरपूर साथ दिया तथा कार्यकर्त्ताओं की उम्मीदों से भी ज्यादा आगे बढ़कर गतिशीलता दिखायी। संस्था की ओर से इस गतिशीलता को सही दिशा व नेतृत्व प्रदान किया गया होता तो आज इन चारों समूहों का काफी विकास हो चुका होता। लेकिन इसके अभाव में चारों समूहों से जुड़ी महिलाएं बीच भंवर में अटकी हुई हैं। आत्मनिर्भर बनने और स्वरोजगार से जुड़ने के लिए समूह से जुड़ी इन महिलाओं की सुधि लेनेवाला फिलवक्त कोई नहीं है। लिहाजा महिलाएं खुद को ठगी–ठगी सी महसूस करने लगी हैं। संस्था द्वारा यहां की महिलाओं के साथ बरते जा रहे उपेक्षात्मक रवैये के कारण समूहों की न तो विधिवत और नियमित बैठक हो पा रही है और न ही महिलाएं किसी तरह के रोजगार से जुड़ पायी हें। वहीं महिलाएं लोन लेने और देने के सवाल पर आपस में ही उलझने लगी हैं। पर इन सब समस्याओं का समाधान करने और महिलाओं को दिखाये गये सब्ज बाग को पूरा करने की

दृढ़ संकल्प का दस्तावेज है।

पौधे तो लगा दें, पर उन्हें बचायें कैसे ? यह सबसे अहम सवाल है पूरी दुनिया के वृक्षारोपण अभियान के तंत्र के सामने। इस सवाल का हल साहीटांड की महिलाओं ने अपने ढंग से निकाला। सुबह छह बजे ही महिलाओं का एक जत्था हाथों में टांगी लेकर जंगलों की रक्षा के लिए निकल पड़ता है। दिन के दस बजे दूसरा जत्था निकलता है। शाम छह बजे से रात भर जंगलों की रक्षा का जिम्मा पुरूषों का है। इन इलाकों में पौधों के बड़े होने तक गाय–गोरू चराने पर भी रोक लगा दी गयी है। आसपास के कुछ इलाकों में जहां अब तक पेड़ बचाने की चेतना नहीं आयी है, उनके साथ कई बार झगड़े की भी नौबत आ जाती है। ऐसा तब होता है जब उन्हें पेड़–पौधों के दुरूपयोग से रोका जाता है ।

साहीटांड गांव झारखंड के उन असंख्य बदनसीब गांवों में एक है जहां अब तक विकास की कोई किरण नहीं पहुंची। गांव में कोई स्कूल तक नहीं। बच्चे पढ़ना चाहें तो दाढ़ीडीह जाना पड़ता है जहां तक पहुंचने में एक घंटा लगता है। बिजली की तो खैर बात ही दूर। गांव के किसी भी व्यक्ति के पास लालकार्ड भी नहीं। जाहिर है कि विकास अभी कोसों दूर है इस गांव से, जबकि महिलाओं की चेतना ने उम्मीद के नये दरवाजे अवश्य खोल दिये हैं। दूसरी ओर, पर्यावरण संरक्षण पर घंटों उपदेश देनेवालों तथा कटते पेड़ व बिगड़ती पारिस्थितिकी की चिंता से दुबले होते 'सभ्य' मानवों के लिए एक सीख लेकर आयी हैं साहीटांड गांव की महिलाएं।

लाभ योजना की सुविधा मिलने की घटना आसपास की सभी महिलाओं के लिए एक बड़ी मिसाल के बतौर थी और सबको लगने लगा था कि इस तरह एकजुट होने तथा पहलकदमी का परिणाम अवश्य मिलेगा। इस भरोसे के कारण शांति मुर्मू के नेतृत्व में महिलाएं तेजी से गोलबंद होने लगीं। जल्द ही एक स्वयं सहायता समूह का गठन कर लिया गया। महिलाओं ने इसका नाम रखा – 'तुलसी गाती दाड़ीम'।

इस समूह की अध्यक्ष सावित्री मरांडी ने आसपास की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को लाभों तथा जरूरत के बारे में भलिभांति अवगत करा दिया। सावित्री मरांडी के अनुसार महिलाओं को बचत तथा ऋण के महत्व की भी जानकारी दे दी गयी है। हर हफ्ते थोड़ी–थोड़ी रकम बचाकर अब तक समूह ने लगभग दो हजार रूपये जमा करा दिया। दूसरों के लिए यह रकम भले ही मामूली हो, समूह के लिए यही रकम एक बड़ी शुरूआत की आधारशिला बन गयी है। महिला सदस्यों को बेहद मामूली ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के नियम बनाये गये हैं।

महिलाओं की इस पहलकदमी को ठोस व व्यापक आधार देने के उद्देश्य से 'मानवी' ने इस समूह को पैक्स कार्यक्रम से जोड़ दिया है। इन महिलाओं को मधुमक्खी, मुर्गीपालन से लेकर अत्याधुनिक कृषि कार्य तक के प्रशिक्षण दिलाये गये। जिला मेसो विभाग से मधुमक्खी एवं बक्से भी उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही, खेतों में सिंचाई के लिए किसानों को पंप सेट मुहैया कराये गये हैं। कृषि योग्य कुल असिंचित क्षेत्र 99.77 के लिए निकट के जोरिया से सिंचाई की व्यवस्था की गयी है।

यह सारा कुछ शांति मुर्मू की पहल से हुआ है। लिहाजा, गांव के लोग उसके प्रयासों की सरहाना करते नहीं थकते। 275 महिलाओं तथा 256 पुरूषों की आबादी वाले इस गांव में करीब पचास महिलाएं मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़ी हैं। संताल एवं पहाड़िया बहुल इस गांव की अन्य महिलाएं मुर्गीपालन एवं सब्जी की खेती करके अपने घर की आय बढ़ाने में जुटी हैं। खुद शांति मुर्मू ने इस वर्ष अपने खेत में भिंडी की खेती करके लगभग एक हजार रुपये की आमदनी की। शांति मुर्मू कहती हैं कि पहले किसी तरह सिर्फ खेती या मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब रोजगार के कई प्रकार के साधनों की व्यवस्था हो जाने से काफी राहत मिल है। यह सारा कुछ

इसलिए हो सका कि शंति मुर्मू ने साल भर पहले अपने गांव से जिला मुख्यालय तक का सफर तय किया। अब तो वह अपने आस पास के इलाकों के जरूरतमंद ग्रामीणों के वाजिब हक के लिए प्रायः हर सप्ताह प्रखंड तथा जिले के सरकारी कार्यालयों में जाती हैं तथा ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए खूब दौड़–भाग करती हैं। इसलिए लोग कहते हैं – शांति की पहल ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी।

■

इकाइयों के खुलने या बंद होने के बावजूद साहीटांड जैसे गांव के आदिवासियों के जीवन का मुख्य आधार आज भी जंगल पर ही टिका है। जबकि जंगल–माफिया द्वारा अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई के कारण जंगलो का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। जंगलों तथा आसपास के इलाको में रहने वाले लोगों द्वारा भी मनमाने ढंग से पेड़ों का दुरूपयोग करने, मवेशी चराने वगैरह के कारण पेड़ों की संख्या घटती जा रही है। वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया भी जाता है तो जंगलों मे चरने गये जानवर उन पौधों को नष्ट कर देते हैं।

यह तस्वीर अधिकांश क्षेत्र के जंगलों की है। लेकिन साहीटांड गांव की महिलाओं में वनों के संरक्षण के प्रति आयी चेतना ने अपना रंग दिखाया है। महिलाओं ने पौधे लगाने तथा पेड़ बचाने का अभियान चला रखा है। महिला समिति की अध्यक्ष मंजू देवी बताती हैं कि उनका यह प्रयास पिछले कई वर्षों से चल रहा है क्योंकि उनकी समझ में यह बात आ गयी है कि जंगल है तो जीवन है। मंजू देवी के अनुसार शुरू–शुरू में तो महिलाओं को वन विभाग के लोगों की ओर से कोई खास प्रोत्साहन नहीं मिला, लेकिन वर्ष 2003 में फॉरेस्टर से मदद मिलने के कारण उनका अभियान तेज हो गया। पंद्रह महिलाओं की समिति बनी। वन विभाग की ओर से समिति को चार कुरसियां और एक दरी दी गयी। थोड़े बरतन भी। गांव के ही जगदीश उरांव को कैटल गार्ड में भरती कर लिया गया। सितंबर 2004 से उसे सत्रह सौ रूपये महीना मिलता है।

मंजू देवी बताती हैं कि परन देवी, सुगनी, शनीचरिया, लालो, सुशीला देवी, बंधन, पार्वती, सोनारी, चांदो, गुरवारी, इंदो, मनमतिया इत्यादि महिलाओं ने किस तरह पूरी मेहनत से समिति के हर काम को बखूबी पूरा किया। वन विभाग से मिले पौधों के जरिये महिला समिति ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया है। दिसंबर 2003 में गांव के पूरब की ओर पचास हजार वृक्ष लगाये गये। सितंबर 2004 में उत्तर की ओर पचास हजार वृक्ष लगाये गये। लिप्ट्स, शीशम, गम्हार, एकासिया, चोकंडी, बांस, बबूल, सखुआ इत्यादि पेड़ हैं इनमें जमीन वन विभाग की, पौधे भी वन विभाग के। लेकिन मेहनत ग्रामीणों की, संरक्षण ग्रामीणों द्वारा। आज इस गांव के आसपास दूर–दूर तक चार–चार, पांच–पांच फीट ऊँचे पेड़ दिखाई पड़ते हैं जो महिलाओं की कड़ी मेहनत व

साहीटांड की आदिवासी महिलाएं

पेड़ से जुड़ी जिंदगी या जंगल बचाने की जिद

■ दिनेश राजगढ़िया/दीपक प्रसाद

हम सब तो जंगल के ही हैं। जंगल ही नहीं रहेगा तो हम आदिवासी लोग कहां रहेंगे। इसलिए हमलोग अपना जंगल बचाने के लिए इतनी कोशिश कर रही हैं।

टूटी—फूटी हिंदी और नागपुरी भाषा के मिश्रण के सहारे सुशीला देवी जब यह बात कह रहीं थी, जब आसपास खड़ी अन्य आदिवासी महिलाएं भी सहमति में अपने गरदन हिला रही थी। सुगनी देवी अपनी ओर से कुछ और जोड़ते हुए कहती हैं कि जंगल रहेगा तो बहुत काम आयेगा, घर बनाने में, हल बनाने में, फल—फूल और छाया मिलेगी, पानी भी बचेगा, जलावन और दातुन, पत्ता—दोना, सब में काम आयेगा जंगल, इसी से तो काम चलता है हमलोग का।

झारखंड के खनिज एवं संपदा से भरपूर हजारीबाग जिले के औद्योगिक प्रखंड पतरातू की कोनो पंचायत में है साहीटांड गांव। पतरातू—रामगढ़ मार्ग पर थर्मल पावर के ठीक दूसरी ओर एक पीपीसी सड़क जाती है पारगढ़ा की ओर। इसी सड़क पर करीब चार किलोमीटर बाद है साहीटांड़। पतरातू मेनरोड से लेकर न्यू मार्केट तक कोई नहीं जानता साहीटांड़ गांव का नाम। गांव तक पहुंचने के लिए किसी ग्रामीण की सहायता लेनी पड़ती है। यहां महज 30—40 घर हैं आदिवासियों के। पर यही उरांव जनजाति के लोग शोर—शराबे और मिथ्या प्रचार से दूर लंबे समय से एक नया इतिहास रचने में व्यस्त हैं।

यहां की आदिवासी महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर वन संरक्षण का दायित्व बखूबी संभाल लिया है। पतरातू प्रखंड में बड़ी संख्या में कोयला खदानों के साथ ही पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री, बिहार एलॉय स्टील लिमिटेड जैसे कारखानों तथा अन्य औद्योगिक

चलंत पुस्तकालय

तीस गांवों में जारी है जागृति का नया अभियान

■ शैलेन्द्र सिन्हा

तेजी से बदलते समाज में आज बड़े शहरों तक में कोई लाइब्रेरी अमूमन नजर नहीं आती। कस्बों और गांवों में तो इसकी उम्मीद ही बेकार है। लेकिन झारखंड के पाकुड़ जिले के तीस गांवों के लोगों के लिए नयी जागृति का एक अनूठा अभियान आरंभ हुआ है — 'चलंत पुस्तकालय'। जहां आप पुस्तकालय शब्द सुनते ही किसी बड़े से भवन में ढ़ेर सारी किताबों की कल्पना करते हैं। वहीं यह चलंत पुस्तकालय साइकिल पर खुद चलकर ग्रामीणों के दरवाजों तक पहुंचता है। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड की तीन पंचायतों— देवीनगर, बड़कियारी तथा बिराकिटी के तहत तीस गांव के लोगों के लिए यह एक रोमांचक अनुभव है।

चलन्त पुस्तकालय का यह अनूठा अभियान पैक्स कार्यक्रम के तहत 'जुड़ाव' स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित है। इस पुस्तकालय को तीन स्वयं सेवक चला रहे हैं, जो प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक साइकिल से घूमकर पुस्तक एवं अखबार पहुंचाते हैं। प्रतिदिन ये तीन स्वयंसेवक 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। महेशपुर प्रखंड के चलंत पुस्तकालय से लाभान्वितों की संख्या लगभग 155 है। तीन पंचायत के तीस गांव के लोग अब इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। महेशपुर प्रखंड की कुल आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 140665 है, जिसमे महिला 16 प्रतिशत और पुरूष 37 प्रतिशत ही साक्षर हैं। आदिवासियों की आबादी 53 प्रतिशत है।

देवीनगर पंचायत के मोटालपोखर, देवीनगर, खरीड़ीह, लालचुआं, आखरा, शोल, डोमनडीह, पाथरदाहा, परतापपुर, टीटीडंगारू एवं गांगमुंडी गांव के चलंत पुस्तकालय मइकेल हेम्ब्रम देखते हैं। वे प्रतिदिन साइकिल से अखबार, पुस्तक एवं सरकारी योजना की पुस्तकें लोगों तक पहुंचाते हैं। पंचायत में उन्होंने सूचना केन्द्र बना रखा है, जहां पुस्तकालय के सदस्य जुटते

हैं। माइकेल लोगों के बीच जागरूकता का कार्य भी कर रहे हैं। माइकेल ने कहा कि देवीनगर पंचायत के लोग आवागमन के अभाव में प्रखंड मुख्यालय तक नहीं जा पाते हैं। माइकेल हेम्ब्रम मैट्रिक पास हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। वे बताते हैं कि 'प्रारंभिक दिनों में किसी भी प्रकार से लोग सदस्य बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी लगातार साइकिल यात्रा एवं निवदेन से लोग सदस्य बने। आज चलंत पुस्तकालय का लाभ वे उठा रहे हैं और वे उनके साथ जुड़ रहे हैं। पैक्स कार्यक्रम के तहत एक साल पहले प्रारंभ चलंत पुस्तकालय से लोगों को जागरूक बनाने में काफी मदद मिल रही है। पंचायत सूचना केन्द्र में लोग बैठकर गांव की समस्या एवं डायन जैसे अंधविश्वास पर चर्चा करते हैं।

बड़ी कियारी पंचायत में हाथीमारा, खुतुकपुर, बड़किंयारी, दतियापुर, दुमका, डांगा, भाग बांध, कसिया, डांगा, मायेर बांटा, रघुनाथपुर, सिन्दु, पथराडांगा, बामनपोखर, एवं बोडालपोखर गांव का काम स्टेनशीला सोरेन देख रही है। स्टेनशीला खुद मैट्रिक पास है, लेकिन इन गांवों में अशिक्षित महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है। वह महिलाओं को जागरूक कर सरकारी योजनाओं के बारे में बताती है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में भी कार्य कर रही है। स्टेनशीला सोरेन ने बताती हैं कि हम 'चलन्त पुस्तकालय' के माध्यम से पंचायती राज के बारे में भी जानकारी देती है। महिलाओं की कई कानूनी सहायता दिलाने एवं कानूनों की जानकारी भी वह स्वयं देती है। चलंत पुस्तकालय में उपलब्ध अखबार को कभी–कभी पढ़कर सुनाना भी पड़ता है। बड़ी कियारी पंचायत के सभी गांवों में अब उसका इंतजार पुरूष एवं महिलाएं करती है। एक वर्ष के अंदर एक बदलाव नजर आ रहा है।

बिरकिटी पंचायत के बिरकिटी, सीतारामपुर, दराजपुर, गोलाबारी, खोसालपुर, बास्ता और छत्तीसगाड़िया गांव के चलंत पुस्तकालय का काम मकदलीना सोरेन देखती है। वे भी प्रतिदिन लगभग 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर पुस्तकालय को लोगों तक पहुंचाती हैं। मकदलीना कहती है कि 'सरकार की शिक्षा नीति के बावजूद साक्षरता का प्रतिशत नहीं बढ़ा है। आदिवासी स्त्रियों की शिक्षा का दर बहुत कम है। साक्षरता के नाम पर खर्च के बावजूद करोड़ों लोग आज भी निरक्षर है।' बिरकिटी पंचायत के संबंध में

मकदलीना कहती है ''सरकारी योजना के बावजूद गांवों को रोजगार के लिए दूसरे प्रांत जाना पड़ रहा है। चलंत पुस्तकालय के क्रम में प्रतिदिन साइकिल से घूमने के क्रम में ग्रामीण बताते है। कि उन्हें अंत्योदय एवं अन्पूर्णा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी योजना का पोल–खोल का पता गांव में ही चलता है।''

पैक्स कार्यक्रम के तहत संचालित चलन्त पुस्तकालय 'विचार आपके द्वार' के माध्यम से ग्रामीण लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रखंड समन्वयक कृष्ण कमल कहते हैं–'एक वर्ष के अंदर चलन्त पुस्तकालय इस प्रखंड में खासा लोकप्रिय हो गया है। चलन्त पुस्तकालय के माध्यम से लोगों में नई जागृति आई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं विकास के नए आयाम गढ़ रही हैं। जन वितरण प्रणाली को दुरूस्त करने की महिलाओं ने ठानी है। जन जागरण अभियान के माध्यम से युवा नेतृत्व उभर रहा है।'